



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 502 वर्ष 2026

राम दयालयाची

बनाम

उप संचालक चकबंदी, आजमगढ़प्रतिवादी

याची के अधिवक्ता: संजय कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा बोर्ड पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"क. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें उप संचालक चकबंदी, आजमगढ़ को उनके न्यायालय में 23.12.2019 से लंबित पुनर्स्थापन मामला संख्या 1937/2019, राम दयाल बनाम सीताराम, अंतर्गत धारा 48(1) यू.पी.सी.एच. एक्ट 1953 को शीघ्रता से, अधिमानतः निर्धारित अवधि के भीतर तय करने का निर्देश दिया जाए ताकि न्याय हो सके; अन्यथा याची को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मामला काफी लंबे समय से विचार के लिए लंबित है; हालाँकि, इसे शीघ्रता से तय कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश जारी किया जाता है।
5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, जिसमें वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, उप संचालक चकबंदी, जिनके समक्ष उपरोक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को निर्देश दिया जाता है कि वे कानून के अनुसार इसे शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से पांच महीने की अवधि के भीतर तय करें, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।
6. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन निस्तारित किया जाता है।

फरवरी 5, 2026

विनय

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"